worked out, for 1997-98, the first full year of BMS implementation.

Grassroot Planning in States

1826. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how far the Central Planning Department has taken up implementation of the concept of grassroot planning in States;

(b) whether this concept of grassroot planning can be reflected in the preparation of the Ninth Five Year Plan; and

(c) whether the Planning Commission has prepared the Ninth Five Year Plan with the spirit of the 73rd and 74th Constitution (Amendment) Acts, to devolve financial powers at the grassroot level of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (c) The setting of Panchayati Raj Institutions (PRIs) consequent to the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts marks a watershed with implementation of the concept of grassroot planning in the states. As a consequence of these Acts, State Governments have enacted enabling legislations providing for elected bodies at the village, intermediate and district level with adequate representation from the weaker sections and women. All the states have constituted State Finance Commissions and State Election Commisssions. The Approach Paper to the Ninth Plan especially outlines the role of PRIs in decentralised planning. The formulation of the Ninth Five year Plan is still underway in the Planning Commission. However, financial devolution to PRIs—have already been initiated. Funds for Jawahar Rojgar Yojana are directly going to PRIs in the ratio of 65:15:20 for Gram Panchayat, intermediate Panchayat and Zilla Parishad respectively.

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

1827. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में विभिन्न राज्यों में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में अनुमानतः कितने रोजगार सृजित किए गए;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) क्या गुजरात राज्य में जहां निजी क्षेत्र में कम रोजगार के अवसर सृजित हुए है, रोजगार बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 1987-88 में एनएसएसओ(43वें दौर) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से उपलब्ध कराई गई है। 1987-88 के एनएसएसओ अनुमानों से यथा-उपलब्ध, सामान्य सिद्धान्त स्थिति के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रकों/दोनों में सृजित नौकरियां 1993-94 में एनएसएसओ (50वें दौर) द्वारा कराए गए पंचवर्षीक सर्वेक्षण से उपलब्ध कराई गई है। 1993-94 के एनएसएसओ अनुमानों से यथा उपलब्ध सामान्य सिद्धान्त स्थिति के अनुसार राज्यवार रोजगार संलग्न विवरण में दिए गये है। (नीचे देखिए)।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना से पहले देश में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1993-94 में एनएसएसओ (50वां दौर) द्वारा कराए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण से उपलब्ध कराई गई है। 1993-94 के एनएसएसओ अनुमानों से यथा उपलब्ध, सामान्य सिद्धान्त स्थिति के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(घ) गुजरात में रोजगार सृजन के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की जा रही। यद्यपि सरकार सम्पूर्ण देश में कई स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

कार्यान्वित कर रही है, जिसमें गुजरात राज्य को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वतः रोजगार की एक स्कीम है अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और मजदूरी रोजगार के लिए दो स्कीमें अर्थात् जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) और रोजगार आश्वासन स्कीम(ईएएस) है। नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) शहरी क्षेत्रों में और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) ग्रामीण शहरी दोनों में कार्यान्वित की जाती है।

विवरण

राज्यवार रोजगार और बेरोजगारी ('000 व्यक्ति)

राज्य	रोजगार		बेरोजगारी	
	1987-88	1993-94	1987-88	1993-94
1. आन्ध्र प्रदेश	27682	34391	1146	454
2. अरूणाचल प्रदेश	309	410	1	5
3. असम	6703	7116	402	590
4. बिहार	24653	28558	716	771
5. गोवा	359	456	35	57
6. गुजरात	14708	16753	396	325
7. हरियाणा	4622	4881	277	143
8. हिमाचल प्रदेश	2030	2286	69	116
9. जम्मू और कश्मीर	2189	2485	60	74
10. कर्नाटक	17215	20080	421	383
11. केरल	9256	10133	1890	1139
12. मध्य प्रदेश	24964	28560	402	431
13. महाराष्ट्र	29620	35132	903	855
14. मणिपुर	477	648	11	17
15. मेघालय	673	989	3	4
16. मिजोरम	252	295	0	2
17. नागालैंड	70	358	3	10
18. उड़ीसा	11193	12483	543	381
19. पंजाब	6033	6666	258	163
20. राजस्थान	17070	18616	447	109
21. सिक्किम	144	163	5	2
22. तमिलनाडु	24266	26747	1279	886
23. त्रिपुरा	715	943	32	36
24. उत्तर प्रदेश	42666	48022	761	711
25. पश्चिम बंगाल	19819	23314	1286	1228
26. अ० व नि० द्विपसमूह	85	111	3	8
27. चण्डीगढ़	213	289	20	22
28. दादरा व नगर हवेली	58	58	0	1
29. दमन और दीव	29	39	3	1
30. दिल्ली	2592	3539	133	49
31. लक्ष्यद्वीप	9	16	2	4
32. पांडिचेरी	253	301	18	17
अखिल भारत	290927	334838	11525	8994

स्रोतः एनएसएसओ (1987-88) 43वां दौर और 50व (1993-94) दौर के परिणाम।